नं. जेड-14014/1/2021-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3010921)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 17.10.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सितम्बर, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को **सितम्बर,** 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।

9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

सितम्बर, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में

1. **ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक** दिनांक 12.09.2023 को कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समिति ने भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की।

2. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में **परियोजना स्वीकृत और निगरानी समिति** (पीएस एण्ड एमसी) की बैठक दिनांक 21.09.2023 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संपन्न हुई। इस बैठक में डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत 10 घटकों/कार्यकलापों के संदर्भ में 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1200 करोड़ रूपए से अधिक के प्रस्तावों पर विचार किया गया। अध्यक्ष, परियोजना स्वीकृति और निगरानी समिति (पीएसएमसी), ने डिजिटल इण्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत उत्तरपूर्व के राज्यों जैसे नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, सिक्किम आदि के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। पूर्वोत्तर के राज्यों को सहायता देने के उद्देश्य से बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद को डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए 400 लाख रूपए की मंजूरी दी गई।

विभाग, डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत भूमि अभिलखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण से संबंधित योजना घटकों को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है। कुल 157 जिलों ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है जिनकी संख्या अगस्त, 2023 की शुरूआत में 68 थी।

3. विभाग ने हिन्दी को राजभाषा के तौर पर बढ़ावा देने हेतु 14 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2023 के दौरान **'हिन्दी पखवाड़ा'** मनाया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं की आयोजित की गई जिनमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विभाग के अधिकारियों ने 14 से 15 सितम्बर, 2023 तक पुणे में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित "तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन" में भाग लिया। विभाग ने विभाग के कर्मचारियों के लिए 29.09.2023 को स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ 2.0" पर एक कार्यशाला आयोजित की।

4. विभाग के मीडिया अभियान के हिस्से के रूप में तथा जी-20 बैठक को ध्यान में रखते हुए, विभाग के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभाग ने दिनांक 07.09.2023 को क्रमशः केन्द्रीय सचिवालय तथा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर

वॉटरशेड विकास पर 'टर्निंग बेरन इंटू ग्रीन्स' थीम से तथा डीआईएलआरएमपी के तहत भू-आधार / यूएलपीआईएन के थीम से दो **'सेल्फी बूथ'** स्थापित किए। माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज) महोदय ने 11 सितंबर 2023 को मेट्रो में यात्रा करके सेल्फी पॉइंट का दौरा किया, उन्होंने यात्रियों से बातचीत की तथा लोगों के साथ सेल्फी भी लिए। दौरे के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

5. सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2023 को राजस्थान, केरल, कोलकाता, पंजाब तथा हरियाणा में **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई** की प्रगति पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, विभाग द्वारा व्यय, सूचना प्रबंधन प्रणाली(एमआईएस), अमृत सरोबर तथा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अन्य मुद्दों पर संबंधित राज्य के सीईओ के साथ वीडियो कॉंफेरेंस के माध्यम से दिनांक 06.09.2023 तथा 13.09.2023 को दो समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।

6. विभाग द्वारा अपने सभी तीनों कार्यालय परिसरों अर्थात एनबीओ बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स तथा शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी में स्वच्छता कार्यकलापों तथा लंबित पत्राचारों के निपटान पर **विशेष अभियान 3.0** चलाया जा रहा है। तैयारी चरण के हिस्से के रूप में, लंबित पत्राचारों को चिन्हित करने, स्वच्छता कार्यकलापों, अतिरिक्त सामाग्री तथा फाइलों की समीक्षा का कार्य 15 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक किए गए तथा लक्ष्य निर्धारित किया गया। अप्रचलित तथा अनुपयोगी वस्तुएं, ई-वेस्ट तथा फर्नीचर को इंवेंट्री प्रबंधन के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है तथा ई-नीलामी के माध्यम से उनके निपटान का कार्य आरंभ किया गया है।

7. विभाग ने दिनांक 22 तथा 29 सितंबर 2023 को विभाग के कार्मिकों के लिए शिवाजी स्टेडियम कार्यालय परिसर स्थित रेजुव वेलनेस सेंटर में विख्यात विशेषज्ञ के द्वारा **योगा सत्र** का आयोजन करवाया।

8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, कुल 6382 परियोजनाओं {8214 (स्वीकृत) - 1832 (राज्य को हस्तांतरित)} में से आज तक 6376 परियोजनाएं पूरी की गई। अब तक 6120 परियोजनाओं का एंड लाइन मूल्यांकन किया गया है।

9. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों में हुई प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

i. 6,22,834 गांवों में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण पूरा किया गया।
ii. 5,037 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण किया गया।

iii. 1,31,06,063 भूकर मानचित्रों/एफ़एमबी/टिप्पण का डिजिटलीकरण किया गया।

iv. 4,560 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ भूमि अभिलेखों का एकीकरण किया गया।

v. 3,339 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना की गई।

*****